वर्ष-10//अंक-19// अप्रैल2023

ISSN 2454–5805

₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

कांग्रेस में फूट!

पायलट बने

अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत...

www.aamaadmi.in

Taste Our Delicious Food at your Doorstep!

Order on SWIGGY zomato

www.chaisignal.com

Shop No.24, Katora Talab Garden, Raipur (C.G.)

Follow Us:

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-19// अप्रैल 2023

प्रबंध संपादक : उमेश के बंसी

सर्कुलेशन इंचार्ज : प्रकाश बंसी

रिपोर्टर : नेहा श्रीवास्तव

कंटेंट राईटर : प्रशांत पारीक

क्रिएटिव डिजाइनर : देवेन्द्र देवांगन

मैग्जीन डिज़ाइनर : युनिक ग्राफिक्स

मार्केटिंग मैनेजर : किरण नायक

एडमिनिस्ट्रेशन : निरूपमा मिश्रा

अकाउंट असिस्टेंट : प्रियंका सिंह

ऑफिस कॉर्डिनेटर : योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

अप्रैल 2023

इस अंक में

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला

रायपुर. धान न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी रचा बसा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा.

06

भरोसे का बजट: रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी की मिली सौगात

09

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 06 मार्च को अपने कार्यकाल का पांचवा बजट प्रस्तुत किया गया.

भरोसे का बजट: मुख्यमंत्री बघेल की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण

12

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशील पहल की गई है.

फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ RD के ब्याज दरों में बढ़ोतरी

14

रायपुर. पिछले कुछ समय से बैंक कर्ज महंगा होने के अलावा बैंक योजनाओं में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है.

शिवराजपुर बीच: यहां गोवा से आधे बजट में कर करेंगे खूब इंजाय

25

यह गुजरात का ऐसा बीच जिसको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है ब्लू फ्लैग का दर्जा उन्हीं बीचों को मिलता है जो को दुनिया में बहुत ही साफ और स्वस्छ होते हैं.

देश का सबसे बड़ा डाटा लीक! इस बार एक-दो लाख नहीं, बल्कि 16-8 करोड़ लोग हुए शिकार

30

एक बड़े डेटा लीक (डेटा ब्रीच) का खुलासा हुआ है, जिसका यूजर्स की सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है.

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, समझिए पूरा मामला

37

नई दिल्ली. चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सजा मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है.

कांग्रेस में फूट! पायलट बने अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत...

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

सचिन पायलट की ओर से अनशन किए जाने के फैसले ने देशभर में सियासी हलचल को तेज कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने देशभर के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कुछ नेता विरोध में है. वहीं पायलट के समर्थन में भी कई नेता आ गए हैं.

प्रदेश प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने पायलट के इस कदम को गलत बताया लेकिन रंधावा के बयान पर कांग्रेसी नेताओं ने ही सवाल उठा दिए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पायलट को नसीहत देते हुए पार्टी स्तर पर बात रखने की बातें कही थी. इन केन्द्रीय नेताओं ने भले ही सचिन पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी कदम बताया हो लेकिन देश के कई राज्यों के कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट का समर्थन किया है. उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के नजदीकी आचार्य प्रमोद कृष्णन और छत्तीसगढ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पायलट का खुलकर समर्थन किया. राजस्थान के कई विधायक और मंत्रियों ने भी पायलट के मुद्दों को सही बताया था.

पायलट का समर्थन और रंधावा का विरोध किया आचार्य प्रमोद ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा के बयान पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने रंधावा से पूछा कि रंधावा जी, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा अनशन पार्टी विरोधी कैसे हो गया. आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया कि अडाणी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में लड़ रही कांग्रेस वसुंधरा सरकार के घोटालों का समर्थन कैसे कर सकती है. उन्होंने रंधावा को नसीहत देते हुए लिखा कि हे महात्मात्य, पार्टी नेतृत्व को पार्टी नहीं बनना चाहिए. इससे पहले सचिन पायलट के समर्थन में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने चार पंक्तियां लिखी. हौंसलो का इम्तिहान बाकी है, हरसतों की उड़ान बाकी है, मौसम थौड़ा खराब सा है लेकन, बादलों के पार आसमान बाकी है.

पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी - टीएस सिंह देव

छत्तीसगढ के वरिष्ट कांग्रेसी नेता टीएस सिंह देव ने कहा है कि सचिन पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा पार की हो, ऐसा उन्हें नहीं लगता. सिंह देव ने कहा कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस को फिर से जनता के बीच जाना है. चूंकि पिछले चुनावों से पहले कांग्रेस ने ही जनता से वादा किया था कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराएंगे. अब चुनाव के समय मतदाताओं को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार ने राजे के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच क्यों नहीं करवाई. इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है. जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो जनता भी नेताओं से जवाब मांगती है. लोग कहेंगे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दे. पूर्व में भी जो बातें कही थी, वो पूरी नहीं हुई तो फिर से कांग्रेस को वोट क्यों दें.

Xiaomi ने कीमत में की बड़ी कटौती

Xiaomi ने भारत में अपना फ्लैगशिप Xiaomi 13Pro लॉन्च किया और Xiaomi 12 Pro के लिए कीमतों में बड़ी कटौती की भी घोषणा की. जहां एक तरफ नए फ्लैगशिप को 79,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है.

वहीं, पिछले साल लॉन्च हुए 12 प्रो की कीमत में 10,000 रुपये की कटौती की गई है. Xiaomi ने 12 Pro को अप्रैल 2022 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट, 12GB तक रैम और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया था. स्मार्टफोन 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग से लैस है.

Xiaomi 12 Pro की भारत में नई कीमत, ऑफर्स

शाओमी दो वेरिएंट में आती है और कंपनी ने इसके दोनों वेरिएंट की कीमतों में 10,000 रुपये की कटौती की है. इसके 8GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 62,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और इसकी नई कीमत को बढ़ाकर 52,999 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 66,999 रुपये से घटाकर 54,999 रुपये कर दी गई है. हालांकि, आपको बता दें कि नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी. स्मार्टफोन Couture Blue, Noir Black और Opera Mauve कलर ऑप्शन में आता है. कीमतों में कटौती के साथ ही Xiaomi 12 Pro के खरीदारों के लिए कुछ ऑफर्स की भी घोषणा की गई है. एचडीएफसी बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये की छूट और एक्सचेंज बोनस के रूप में 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट होगी. ग्राहक Xiaomi 12 Pro (रिव्यू) को mi-com, Amazon-in और देश में अधिकृत रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं.

Xiaomi 12 प्रो विनिर्देशों

इसमें 6.72-इंच WQHD+ (1,440x3,200 पिक्सल) E5 AMOLED डिस्प्ले है. यह LTPO टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए 1Hz से 120Hz के बीच रिफ्रेश रेट ऑफर करता है. इसमें डॉल्बी विजन और एचडीआर 10+ के लिए सपोर्ट भी शामिल है. Xiaomi 12 Pro आक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है. इसमें एड्रेनो 730 जीपीयू और 12 जीबी तक एलपीडीडीआर 5 रैम है.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. मुख्य लेंस 50-मेगापिक्सल का Sony IMX707 सेंसर है. इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड शूटर और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूटर भी दिया गया है. फोन में 32 एमपी का सेल्फी कैमरा है. रियर कैमरे से 8K क्वालिटी में वीडियो रिकार्ड किए जा सकते हैं.

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आने वाले इस फोन में 4,600mAh की बैटरी लगी है. यह 120W Xiaomi HyperCharge फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह 50W वायरलेस टर्बो चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. फोन का वजन 205 ग्राम है.

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला

रायपुर. धान न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी रचा बसा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा. राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला राज्य के लगभग 25 लाख किसानों के जीवन में सीधे तौर पर बदलाव लाएगा. इस फैसले से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी. इसका फायदा उद्योग और व्यापार जगत को भी मिलेगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निर्भर है. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य के उद्योग नीति में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है. गांव में खेती-किसानी स्थिति सुधारने, जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि के लिए भी सुराजी गांव योजना लागू की गई है. इस योजना के नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को धरातल पर पूर्ण की जा सके.

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी एक क्रांतिकारी फैसला

मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य में अगले खरीफ सीजन से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी के फैसले से किसानों में काफी उत्साह और खुशी का महौल है. आगामी सीजन में भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि रकबा में वृद्धि होगी. पिछले वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई थी. 5 क्विंटल धान की और खरीदी होने से आगामी सीजन में लगभग 125 से 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में इस साल रिकार्ड 107.53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों की जेब में लगभग 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि पहुंची है. राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के फलस्वरूप निर्धारित समय में चावल की मिलिंग की जा रही है. 61 लाख टन चावल एफसीआई और नान में जमा करने के लक्ष्य के विरूद्ध 43 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है.

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी एक क्रांतिकारी फैसला

राज्य सरकार द्वारा बीते चार वर्षों में लिए गए अनेक किसान हितैषी फैसलों के बदौलत लगातार खेती-किसानी में परिवर्तन आ रहा है. राज्य के किसान आधुनिक खेती की ओर भी तेजी से बढ़ने लगे हैं. राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी से किसान पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं. खेती-किसानी में किसानों की रूचि बढ़ी है. पहले से खेती छोड़ चुके किसान अब फिर से खेती-किसानी की ओर लौटने लगे हैं. खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं के बेहतर मानिटरिंग और किसानों तक योजनाओं की पहुंच से किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है. छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे है. राज्य में ट्रैक्टर सहित अन्य उन्नत कृषि उपकरणों की बिक्री से यह बात साफ हो जाती है. राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उद्यानिकी फसलों को भी बढ़ावा मिल रहा है. इसी प्रकार बागवानी मिशन और मसालों की खेती की ओर भी किसान आकर्षित हो रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है.

सुराजी गांव योजना के तहत गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा रहे हैं. जहां कृषि आधारित तेल मिल, दाल मिल आदि छोटे-छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहीं गोधन न्याय योजना के तहत हजारों-लाखों महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट सहित विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में जोड़ा जा रहा है. गौठान बनने से राज्य में पशुओं की खुली चराई पर रोक लगी है. इससे सिंचाई की व्यवस्था रखने वाले किसान अब दोहरी फसल लेने में सक्षम बने.

समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ी है. वहीं किसानों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ किए गए. उपार्जन केन्द्र बढ़कर 2 हजार 617 हो गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए वर्ष 2018 में लगभग 18 लाख 82 हजार किसानों का कृषि ऋण लगभग 10 हजार करोड़ रूपए माफ किया. इसी तरह 244.18 करोड़ रूपए के सिंचाई कर की माफी ने भी खेती-किसानी और किसानों के दिन बहुराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है.

पिछले चार सालों में विभिन्न माध्यमों से किसानों-मजदूरों और गरीबों की जेब में डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि डाली गई है. इसका परिणाम यह रहा कि कोरोना संकट काल में जहां देश में आर्थिक मंदी रही, वहीं छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती-किसानी और इससे जुड़े उद्यानिकी मत्स्य पालन, पशुपालन, जैसे कार्यों के लिए सहकारी समिति से ऋण प्रदाय करने की योजना और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देने जैसे विविध क्रांतिकारी सिद्ध हो रहे हैं.

लेख- जी.एस. केशरवानी और ओम प्रकाश डहरिया

छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने विशेष पहल : CM बघेल ने किया वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ

पांच सालों में 15 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर विधानसभा में दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना' का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे. इस अवसर पर संसदीय सचिव द्वय शिशुपाल सोरी, चन्द्रदेव प्रसाद राय भी उपस्थित रहेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल विभिन्न वनमंडलों में 'मुख्यमंत्री वृक्षसंपदा योजना' के हितग्राहियों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की है. इस योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है.

1 लाख 80 हजार एकड़ में रोपे जाएंगे पौधे

मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36 हजार एकड़ तथा 5 वर्षो में 1 लाख 80 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी. चिन्हित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाएगा. 5 वर्षो में रोपित सभी प्रजातियो के वृक्ष परिपक्व होने पर उनका मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये होने की सम्भावना है. इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 15 हजार से 50 हजार तक आय सम्भावित है.

इस वर्ष 30 हजार एकड़ रकबे में होगा रोपण

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा. इनमें से क्लोनल यूकलिप्टस का 17 हजार 182 एकड़ में, रूटशूट टीक का 6 हजार 456 एकड़ में, टिश्यू कल्चर का 2 हजार 617 एकड़ में, चंदन का 1 हजार 462 एकड़ में, मेलिया दुबिया का 8 सौ 34 एकड़ में, सामान्य बांस का 7 सौ 37 एकड़ में, टिश्यू कल्चर बम्बू का 6 सौ 7 एकड़ में, रक्त चंदन का 1 सौ 26 एकड़ में, आंवला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में तथा महानीम का 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी होंगे पात्र

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे. इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे. इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे. मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है. इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है.

भरोसे का बजटः रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी की मिली सौगात

- **एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी**
- **बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की होगी स्थापना**
- **बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी और नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की स्थापना का प्रावधान**

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 06 मार्च को अपने कार्यकाल का पांचवा बजट प्रस्तुत किया गया. बजट में विद्यार्थियों से लेकर खिलाड़ियों तक सभी का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, महिला खेलकूद को प्रोत्साहन एवं विभिन्न खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है. राज्य में पारंपरिक खेलों के बढ़ावा दिया जा रहा है. खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम स्तरीय खेल प्रतियोगिता से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के आयोजन के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रूपए की घोषणा की गई है.

इस बजट में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल यथा एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स जैसे खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है. इसी तरह शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी एवं कायाकिंग व केनोइंग खेल अकादमी की भी स्थापना की जाएगी. तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी. नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

बस्तर जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना और कुनकुरी के ग्राम सलियाटोली विकासखण्ड में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास के लिए नवीन मद में 3 करोड़ 70 लाख की घोषणा की गई है. प्रदेश के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की शुरूआत की गई है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्ग के महिला एवं पुरूषों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सफल आयोजन से इन खेलों के प्रति स्थानीय लोगों के रूझान और उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भव्य आयोजन के लिए इस बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है. मुख्यमंत्री द्वारा बजट में राजीव युवा मितान क्लब के लिए 100 करोड़ रूपए तथा राजीव युवा महोत्सव के आयोजन हेतु 08 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है.

लेख : सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

कृषि संबंधी झलकियां : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट में हुई बढ़ोत्तरी

- 26 लाख से अधिक किसानों को 6,800 करोड़ की मिलेगी आदान सहायता
- स्वावलंबी गौठानों समिति के अध्यक्ष-सदस्यों को मिलेगा मानदेय
- छुईखदान की पान खेती को मिलेगी नयी पहचान

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार के बजट में राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों और उनसे जुड़े कृषि और अन्य क्षेत्रों को अधिक मजबूत करने के ठोस कदम उठाये गए हैं. खाद-बीज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है. किसानों को देश-दुनिया में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार से परिचित होने के लिए भी पहल की गई है. साथ ही राज्य में स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया. उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है. बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है.

वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है. इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

राज्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पाद की पैदावार हो इसके लिए आवश्यक है कि बीजों और उर्वरक की गुणवत्ता भी नियंत्रित हो, इसके लिए रायपुर में सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है. इसके अलावा राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है. साथ ही रायपुर के उर्वरक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेटअप से सुसज्जित किया जा रहा है. इससे हम उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने में अधिक मजबूती से काम कर सकेंगे.

बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी.

प्रदेश के गौठानों में 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं. इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है. इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे. गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी.

पशुधन के उपचार देख-भाल के लिए राजधानी रायपुर के ग्राम दतरेंगा में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जा रही है, जिसके सेटअप और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दो करोड़ से अधिक राशि दी गई है. नये जिलों में पशु रोग के अनुसंधान हेतु 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना की जा रही है.

उद्यानिकी किसान नवीन तकनीकों से परिचित हो, इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. जिसके लिए दो करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है.

हमारे किसान हाई टेक हो, इसके लिए गंड़ई में हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी. छुईखदान पारंपरिक रूप से पान की फसलों के लिए जाना जाता रहा है.

इसे प्रोत्साहित करने के लिए और इसके पुनरूद्धार के लिए पान अनुसंधान स्थापना और और इसके लिए दो करोड़ रूपए से बजट देने की गई है.

हमारा प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में देश में एक नयी पहचान के रूप में जाना जा रहा है. इस पहचान को अग्रिम बनाने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है.

सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टाप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है.

भरोसे का बजटः मुख्यमंत्री बघेल की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशील पहल

> रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशील पहल की गई है. इसके साथ ही उन्होंने निराश्रितों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के साथ उभयलिंगी समुदाय का भी विशेष ध्यान रखा है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रूपए की है. इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रूपए प्रति माह करने का प्रावधान बजट में किया है.

बजट के इस प्रावधान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होली का उल्लास दोगुना हो गया है. प्रदेश भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं में हर्ष की लहर है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 50 हजार की गई

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशील पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा बजट में की है. इसके लिए बजट में 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की गई

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह की है. इससे इन वर्गों को जीवन-यापन के लिए सहारा मिल सकेगा.

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नवा पिल्हर योजना होगी शुरू

मुख्यमंत्री ने बजट में उभयलिंगी व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नई पहल करते हुए नवा पिल्हर योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता की जायेगी. इसके लिए बजट में 25 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है.

सियान हेल्पलाईन सेंटर की स्थापना की जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान भी बजट में किया गया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ऐतिहासिक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2 हजार 675 करोड़ रूपए और समाज कल्याण विभाग हेतु 1 हजार 125 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं सहित जरूरतमंद, कमजोर वर्गों के लिए भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने व्यापक प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने इसके माध्यम से 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की परिकल्पना को साकार रूप देने की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है और लोक आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है.

विशेष लेख - सुश्री रीनू ठाकुर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

देश में एक और किफायती इलेक्ट्रिक कार

फुल चार्ज में 320KM

Citroen eC3 का सीधा मुकाबला टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Tata Tigor EV के साथ रहेगा. हालांकि टाटा टिगोर ईवी की कीमत 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है. Citroen eC3 इलेक्ट्रिक कार में 29.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किलोमीटर की रेंज पेश करने का दावा करती है. घर में चार्जर से इस बैटरी को चार्ज करने में अधिकतम 10 घंटे के आस-पास लगते हैं और डीसी फास्ट चार्जर के जरिए इसे 10 से 80 फीसदी चार्ज करने में सिर्फ 57 मिनट का समय लगता है. हालांकि इसे डीसी चार्जर के जरिए 100 फीसदी चार्ज किया जा सकता है.

कैसे हैं फीचर्स और कितनी है कीमत

सिट्रोन इंडिया ने भारत में अपनी फुल इलेक्ट्रिक हैचबैक ईसी 3 को लॉन्च कर दिया है. सिट्रोन ईसी 3 को 11.50-12.43 लाख रुपये, एक्स-शोरूम (दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. देखने में ये कार बिल्कुल अपने पेट्रोल पावर्ड वेरिएंट जैसी ही है, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 12.43 लाख रुपये तय की गई है. कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर रखी है, जिसके लिए 25,000 रुपये की राशि बतौर बुकिंग अमाउंट जमा करनी होगी. फिलहाल, इसकी बुकिंग देश के 25 शहरों में चल रही है.

वारंटी

आपको बता दें कि नई Citroen eC3 को देश के 25 शहरों में La Maison Citroën शोरूम में बेचा जाएगा. खास बात यह है कि ग्राहक इस कार को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की बैटरी पैक पर आपको 7 साल या 1,40,000 किलोमीटर की वारंटी, इलेक्ट्रिक मोटर पर 5 साल या 100000 किलोमीटर की वारंटी और व्हीकल पर 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है.

गर्मियों में बिजली बिल आ रहा है अधिक तो घर में बंद कर दें इन अप्लायंसेज का इस्तेमाल

गर्मियां शुरु हो गई हैं, अगर आप भी हर महीने आने वाले मोटे बिजली बिल से परेशान है तो यह खबर आपके लिए है. कुछ आसान टिप्स का इस्तेमाल करके आप बढ़ते हुए बिजली बिलों पर आसानी से लगाम लगा सकते है. आइए जानते हे कैसे खत्म होगी बिजली बिल की टेंशन. दरअसल सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसे अप्लायंसेज का इस्तेमाल बढ़ जाता है जो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और आप इन्हीं अप्लायंसेज का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करके बिजली के बिल में भारी-भरकम कटौती कर सकते हैं. बस आपको गर्मियों का मौसम शुरु होने से पहले ही इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए.

इलेक्ट्रिक गीजर

कुछ लोग कपड़े धोने के लिए या अन्य कामों के लिए गर्मियों के मौसम में भी इलेक्ट्रिक गीजर इस्तेमाल करते रहते हैं ऐसे में होता है यह है कि इलेक्ट्रिक गीजर जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत करता है और बिजली का बिल बढ़ जाता है. अगर आप बड़े हुए बिजली के बिल पर लगाम लगाना चाहते हैं तो गर्मियों में गीजर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.

इलेक्ट्रिक ब्लोअर

अगर आपके घर का कमरा बड़ा रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिक ब्लोअर काफी अच्छी तरह से काम करता है और पूरे कमरे को गर्म रखता है लेकिन यह बिजली की खपत भी काफी ज्यादा करता है. ऐसे में जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला हो आपको इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए इससे बिजली के बिल में भारी गिरावट देखने को मिलेगी.

इंडक्शन चूल्हा

इंडक्शन चूल्हा कई घरों में लगातार इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस वाले चूल्हे की तुलना में इसे इस्तेमाल करना काफी महंगा सौदा साबित होता है. गैस खत्म हो जाने पर आप इसे आप्शन के तौर पर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप अगर इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको समस्या हो सकती है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है.

इलेक्ट्रिक हीटर

इलेक्ट्रिक हीटर का हम लोग सर्दिओ में बहुत अधिक इस्तेमाल करते है क्यों की घर में कई कमरे होते है और हर एक कमरे के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करते है जिनसे बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. गर्मियों के मौसम में इनका इस्तेमाल बंद करके आप बिजली का बिल आधा कर सकते हैं.

सिर्फ जरुरत पड़ने पर ही एसी की इस्तेमाल करे

अगर आप एयर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए. दरअसल गर्मियों के मौसम की दिक्कत अब पहले से काफी कम हो चुकी है. ऐसे में नार्मल पंखे या कूलर से भी आप काम चला सकते हैं. जरूरत पड़ने पर एयर कंडीशनर भी चलाया जा सकता है हालांकि अब इसकी जरूरत पहले जैसी नहीं है इसलिए अब आप इसका इस्तेमाल बंद करके आपने घर की बिजली का बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं.

ताऊ जी से मिली प्रेरणा... आज 11 साल से मरीजों के दांतों का दर्द दूर कर रहे डॉ. मनीष अग्रवाल

Expert Teeth क्लीनिक पर शहर के लोगों का पूरा भरोसा
क्लीनिक में मौजूद है 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम

रायपुर. अपने ताऊ जी को 40 वर्षों तक क्लीनिक में प्रैक्टिस करते देख शहर के मशहूर डॉ. मनीष अग्रवाल के मन में भी ये ख्याल आया कि उन्हें भी दंत रोग विशेषज्ञ बनना चाहिए. यही कारण है कि उन्होंने एमबीबीएस में होते अपने दाखिले को नहीं लिया और दंत चिकित्सा की पढ़ाई की ओर बढ़ गए और आज वे Expert Teeth क्लीनिक के माध्यम से रायपुरियंस के दांतों की परेशानियों को दूर कर रहे है. बता दें कि क्लीनिक में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ-साथ वेल ट्रेंड नर्सिंग स्टॉफ मौजूद है.

डॉ मनीष बताते है कि उन्होंने स्नातक को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2000 में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, इंदौर में प्रवेश लिया. स्नातक होने के बाद उन्होंने ओरल सर्जरी में मास्टर्स किया. इसके बाद 2010 वे हाईटेक मेडिकल कॉलेज राउरकेला में शामिल हो गए जहाँ उन्होंने ओरल सर्जरी विभाग का नेतृत्व किया.

छत्तीसगढ़ से प्यार था इसलिए आ गए वापस

डॉ. मनीष बताते है कि उन्हें छत्तीसगढ़ से स्नेह है. इसलिए वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेट्रो सिटी से मिलने वाले तमाम ऑफरर्स को एक्सेप्ट न करते हुए रायपुर वापस आ गए और 2011 से समर्पित रूप से वे यहां रैगूलर प्रैक्टिस कर रहे है.

5 एमडीएस डॉक्टरों की टीम मौजूद है Expert Teeth क्लीनिक मे

डॉ. मनीष अग्रवाल बताते है कि छत्तीसगढ़ कॉलेज स्थित सिविल लाइंस में Expert Teeth क्लीनिक मौजूद है. यहां अत्यंत कुशल 5 एमडीएस इन हाउस डॉक्टर की टीम है. जो हर प्रकार के दांतों के ट्रीटमेंट करते है. यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों से लगातार मरीजों का इस क्लीनिक पर निरंतर भरोसा कायम है.

क्या कहते है पेशेंट

Expert Teeth क्लीनिक में रैगूलर ट्रीटमेंट कराने वाले पेशेंट श्री मेहता ने बताया कि 5 साल पहले पायरिया के कारण उनके सारे दांत गिर गए थे और हटाने योग्य नकली दांत खाने और मुस्कुराने के लिए उनका साधन बन गए थे. वे दांत ठीक होने की उम्मीद और साथ में आत्मविश्वास भी खो चुके थे. लेकिन Expert Teeth ने इस महीने उनकी इच्छा पूरी कर दी जब यहां उनके सभी दांतों को डेंटल इम्प्लांट से बदल दिया. अब वे काफी खुश है और अच्छी तरह भोजन का सेवन भी कर पा रहे है.

दंत प्रत्यारोपण से जुड़े कई मिथक

डॉ. मनीष अग्रवाल बताते है कि प्रत्यारोपण (Dental Implant) एक प्राकृतिक दांत के निकटतम संभावित प्रतिस्थापन है. वे न केवल हड्डी के साथ जुड़ते हैं बल्कि प्राकृतिक दांत के समान कार्यात्मक और यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं. डेन्चर के विपरीत, वे स्थायी उपचार के तौर-तरीके हैं जो वर्षों तक चल सकते हैं. उन्हें बार-बार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है और ज्यादातर बिना प्रतिस्थापन के वर्षों तक बने रहते हैं। वे मरीजों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाते हैं। वे उन्हें बेहतर मुस्कुराने और बेहतर खाने में मदद करते हैं।

इम्प्लांट उपचार की लागत के बारे में पूछे जाने पर डॉ. मनीष ने हमें बताया कि ''एक समय था जब इम्प्लांट एक लक्जरी हुआ करता था जिसका केवल अमीर लोग आनंद लेते थे. लेकिन समय बदल गया है. हम एक्सपर्टीथ में स्ट्रामैन, नोबल, ऑस्टेम जैसे सर्वोत्तम इम्प्लांट विकल्प बहुत ही किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं''

उन्होंने आगे कहा कि हाल की प्रगति की गति के साथ बने रहने और नवीनतम और सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प प्रदान करने के लिए एक्सपर्टीथ अब रायपुर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इम्प्लांट सिस्टम ''स्ट्रॉमैन बीएलएक्स'' मरीजों में इम्प्लांट कर रहे है.

डरी सरकार बर्बरता पर उतारू: बृजमोहन

रायपुर. वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संगठन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही मध्यान भोजन रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे की वीडियो जारी होने के बाद उन पर पुलिस द्वारा थाने ले जाकर की गई प्रताड़ना व आपत्तिजनक व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान भूपेश सरकार कितना करती है यहां पर दिख रहा है.नीलू ओगरे जो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सशक्त महिला है. पुलिस ने यह हिमाकत इसलिए कि क्योंकि नीलू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी.

कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए हर किसी से वादा तो कर लिया पर अब वादा निभाने से मुकर रहे है. ऐसे में कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन कर अपने हक की बात आप तक पहुंचाएं तो आप डंडा चला देंगे? उनके बाल पकड़कर सड़क पर खींचेंगे, उनका कॉलर पकड़ेंगे? अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के साथ कांग्रेस सरकार का यह व्यवहार दुर्भावनापूर्ण और आपत्तिजनक है. और ऐसी हरकत डरी हुई सरकार करती है.

बृजमोहन ने सरकार को चेतवानी भरे लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा में जुटे कर्मचारियों के साथ छत्तीसगढ़ की आम जनता भी अब सड़क पर आकर आप से लड़ाई लड़ेगी.

घर बैठे मिलेगी सारी PF डिटेल्स एक मैसेज से मिनटों में हो जाएगा काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडंट फंड (PF) खाताधारकों को ई-पासबुक यानी EPF पासबुक जारी करता है. ईपीएफ पासबुक में योगदान, अर्जित ब्याज, निकासी के साथ पीएफ खाते से जुड़ी सभी जानकारी होती है. डिजिटल इंडिया (Digital India) के इस दौर में मोबाइल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं. जिसके लिए आज से कुछ साल पहले तक लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वक्त बर्बाद होने के साथ-साथ लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होती थीं वो काम अब घर बैठे, कुछ ही मिनटों में, बस कुछ क्लिक्स से हो जाते हैं. अब बैंक डिटेल्स के साथ साथ आप अपने पीएफ की जानकारी भी घर बैठे, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

UAN नंबर वालो को मिलेगी सुविधा

विशेष रूप से PF अकाउंट के लिए ई-पासबुक फैकल्टी केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपना UAN नंबर EPFO पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है. आइए जानते हैं कि EPEO पोर्टल पर UAN नंबर कैसे रजिस्टर करें और ईपीएफ पासबुक तक कैसे पहुंचें.

एसएमएस से मिलेगी डिटेल

EPFO के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर EPFO UAN LAN (भाषा) भेजना है. LAN का मतलब आपकी भाषा से हैं. अगर आपको अंग्रेजी में जानकारी चाहिए तो LAN की जगह ENG लिखना होगा. इसी तरह हिंदी के लिए HIN और तमिल के लिए TAM लिखना है. हिंदी में जानकारी पाने के लिए EPFOHO UAN HIN लिखकर मैसेज करना पड़ता है.

बलरामपुर में कृषि और उद्योग मंत्री ने किया सेहत बाजार 'मिलेट कैफे' का लोकार्पण

रायपुर. बलरामपुर जिला मुख्यालय में मिलेट कैफे का कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने संयुक्त रूप से किया. उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर लोगों आग्रह पर मिलेट कैफे में रागी का डोसा बना कर लोगों का दिल जीत लिया. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर के थालियों में अब स्वाद के साथ-साथ पौष्टिकयुक्त मिलेट भी परोसना शुरू हो जाएगा.

इस मौके पर मंत्री द्वय चौबे और लखमा ने मिलेट कैफे में तैयार किये गए व्यंजनों का लुप्त उठाया. इस मौके पर मंत्रीगणों ने सुराजी गांव योजना के तहत जिले के बड़कीमहरी में गोबर से निर्मित पेंट यूनिट का लोकार्पण किया. बलरामपुर शहरी गौठान में संचालित इस गोबर पेंट यूनिट में तीन महिला स्व सहायता समूह की 30 महिलाएं शामिल है. इस यूनिट से प्रतिदिन 800 लीटर पेंट का निर्माण होगा. जिले के पहले पेंट यूनिट का गोबर पेंट ग्रीन अर्थ एन्ड ग्रीन फुट पेंट (एएलएफ) के नाम से मार्केट में उपलब्ध रहेगी. गौरतलब है कि बलरामपुर जिला जिला प्रशासन द्वारा लोगों को आकर्षित और मिलेट के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मिलेट कैफे का नाम सेहत बाजार के रूप में रखा गया है.

इसके लिए मंत्री चौबे ने कलेक्टर की प्रशंसा की.

मंत्री चौबे ने कहा कि वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब की थालियों से पौष्टिकता कब गायब होती जा रही है, हमें पता ही नहीं चला रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदृष्टि सोच से राज्य सरकार मिलेट मिशन योजना प्रारंभ की है. योजना के तहत बलरामपुर जिले में खोला गया यह सेहत बाजार लोगों के स्वास्थ और सेहत के लिए एक अनुभव पहल है. उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस मौके पर मिलेट कैफे में रागी का डोसा तैयार कर लोगों का दिल जीत लिया. बलरामपुर जिले की इस सेहत बाजार की खासियत है कि यहां रागी और कोदो निर्मित रागी का डुस्का, इडली, दही बड़ा, सांभर बड़ा, रागी के लड्डू, रागी के कुकीज, कोदो की खीर व सिंघाड़े का हलवा जैसे व्यंजन उपलब्ध है. सेहत बाजार का संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की माँ महामाया महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों के माध्यम से मिलेट्स पर आधारित मिलेट मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

विधायक विकास उपाध्याय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हमर क्लीनिक का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया

रायपुर. रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. विधायक विकास उपाध्याय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडी नगर में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया, साथ ही पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन शहरी एंड हेल्थ वेलनेस सेन्टरों की स्थिति से भी अवगत् हुये. उक्त निरीक्षण के दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं इंजीनियर को कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर क्षेत्र की जनता को लाभ देने हेतु निर्देशित किया.

विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि पश्चिम विधानसभा अन्तर्गत....

1. जरवाय हीरापुर में,
2. आर.डी.ए. कॉलोनी हीरापुर,
3. सन्यासी पारा (बाजार चौंक) में
4. शिवांनद नगर खमतराई
5. विकास नगर, गुढ़ियारी
6. सतनामी पारा, साँईनाथ कॉलोनी कोटा
7. टाटीबंध
8. ईस्कॉन टेम्पल टाटीबंध
9. देवार पारा कुकुरबेड़ा में
10. डूमर तलाब
11. मंगल बाजार कुंदरा पारा में
12. मिनी माता चौंक गुढ़ियारी
13. हाण्डीपारा हाण्डी तालाब के पास
14. रामकुण्ड इण्डियन क्लब के पास
15. गीता नगर उड़िया बस्ती में तालाब के ऊपर
16. मंगल बाजार ठाकुर प्यारेलाल वार्ड मे
17. डंगनिया में,
18. तरूण नगर, डंगनिया
19. बाँसटाल, रायपुरा
20. सत्यम विहार, रायपुरा
21. सरोना में
22. चन्दनडीह में
23. संजय नगर सरोना में

इत्यादि स्थानों में शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में निर्माण हो रहे हमर क्लीनिक का जल्द ही क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें लोग अपनी छोटी-छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का समाधान तुरंत करा सकेंगे. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित रहे.

"भरोसे का बजट" सभी वर्गों के हित का बजट : मंत्री अमरजीत भगत

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 2023-2024 का बजट पेश किया गया, इस बजट को भरोसा का बजट नाम दिया गया. बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा पेश किया गया बजट भरोसा का बजट है, ये बजट सभी वर्गों के लिए खुशहाली का बजट है.

अमरजीत भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता का आय बढ़ाने वाला और महंगाई से राहत देने वाला बजट है. हमारी सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरी है, पूरा करते हुए सरकार ने अपने छतीसगढ़ के भविष्य को सुदृढ़ किया हैं. बजट में ग्रामीण क्षेत्र शिक्षित बेरोजगारों को 2500 का प्रावधान है. राजीव गांधी सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ है, राजीव गांधी ग्रामीण योजना का नगर पंचायत क्षेत्रो सुरक्षा पेंशन योजना की राशि (प्रतिमाह 500 रु.) की गई है. लाइट मेट्रो सेवा शुरू की सभी वर्गों की मौजूदा मांगो को कार्यकाल के आखिरी बजट में करने बड़ी राशि का प्रावधान एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने किसान न्याय योजना में इनपुट रुपये का प्रावधान किया गया भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के लिए विस्तार, सामाजिक मे 43 प्रतिशत की वृद्धि दुर्ग से नवा रायपुर के लिए जाएगी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के रुपए प्रतिमाह, मिनी 7500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी मितानीनों के लिए रू. 2200 कोटवारों के लिए सेवा भूमि के 4500 रू. 5500, रू. 6000 रू. 3000 प्रतिमाह. मध्यान्ह रसोईयों हेतु रू. 1800 स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 प्रतिमाह. स्वावलंबी गोठानों हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह का प्रावधान है.

मानदेय में वृद्धि कर 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहायिका को 5000 प्रतिमाह. अतिरिक्त प्रतिमाह. ग्राम आधार पर रू. 3000, रू. प्रतिमाह. ग्राम पटेलों के लिए भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिमाह. विद्यालयों में कार्यरत 2800 प्रतिमाह. होमगार्ड से अधिकतम रू. 6,420 की संचालन समिति के अध्यक्ष

मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के विभागों से संबंधित 4529.37 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित

रायपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के विभागों के लिए प्रस्तुत अनुदान मांगों के लिए कुल 4529 करोड़ 37 लाख 2 हजार रूपए की राशि आज यहां विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दी गई है. स्वीकृत अनुदान मांगों में मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय हेतु 15 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि पारित की गई है. मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण हेतु 1198 करोड़ 86 लाख 50 हजार रूपए की राशि और मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3111 करोड़ 27 लाख 56 हजार रूपए और मांग संख्या 18 श्रम विभाग की अनुदान मांगों के लिए 203 करोड़ 88 लाख 96 हजार रूपए की अनुदान मांग पारित की गई है. विधानसभा में अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास हेतु एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिससे नगरीय निकायों को बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि शहरों में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे. डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकायों को 941 करोड़ रूपए की राशि जारी करने की घोषणा की गई है. जिसमें नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रूपए, भिलाई को 60 करोड़ रूपए, बिलासपुर को 50 करोड़ रूपए, दुर्ग को 25 करोड़ रूपए तथा भिलाई-चरोदा, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर को 20-20 करोड़, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रूपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा राज्य की सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ रूपए और नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस राशि से शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और आधुनिक शौचालयों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च की जाएगी.

नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत नव युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध कराने के साथ ही आजीविका एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु पौनी-पसारी बाजार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है. शहरों में रीपा की तर्ज पर अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क लगाए जाएंगे. साथ ही शहरी गौठानों को मल्टीपरपज एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा. डॉ. डहरिया ने बताया कि स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2022 में भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु द्वितीय स्वच्छतम राज्य का खिताब मिला है. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में छत्तीसगढ़ को देश के स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. डॉ. डहरिया ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सभी नगरीय निकायों में लोगों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैम्प के माध्यम से चिकित्सकों की टीम द्वारा मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाईयां एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना के तहत बहुत कम रेट पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाईयां नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने जल आर्वधन योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है. डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है. सबके लिए आवास मिशन के तहत आवासों का निर्माण किया जा रहा है. इसी तरह से राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. श्रमिकों के स्वास्थ्य, बच्चों एवं बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. जिससे राज्य के श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं.

इन ब्लड ग्रुप वालों का दिमाग होता है सबसे तेज, ये ब्लड ग्रुप वाले आसानी से गुस्सा हो जाते है?

रायपुर. हर एक व्यक्ति की शारीरिक संरचना के साथ साथ शरीर में मौजूद चीजों में भी कई तरह के बदलाव पाए जाते हैं. जिसका प्रभाव व्यक्ति के पूरे शरीर पर पड़ता है. इसी क्रम में अगर बात की जाए, तो हर व्यक्ति का दिमाग समान नहीं होता है. किसी का दिमाग बहुत तेज होता है तो वह न्यूटन बन जाता है और किसी किसी का दिमाग साधारण काम करता है, तो वह सामान्य जीवन जीता रहता है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उसका दिमाग किस कैटेगरी में आता है.

अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि किसका दिमाग सबसे तेज होता है. कौन सा व्यक्ति सबसे चालाक होता है. चतुर और बुद्धिमान होता है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ब्लड ग्रुप को लेकर ये रिसर्च किया था. इसमें सभी ब्लड ग्रुप के लोगों पर स्टडी की गई. इन लोगों के ब्लड सैंपल लेकर रिसर्च किया गया था और इंसान के दिमाग के बारे में जानकारियां जुटाई. ब्लड ग्रुप के हिसाब से शरीर की संरचना थोड़ी अलग होती है और इससे आपके शरीर के अंगों पर भी असर पड़ता है. इससे आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है.इस रिसर्च में पाया गया कि B पॉजिटिवश और O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों का दिमाग दूसरों से ज्यादा तेज था.

कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों का दिमाग होता है सबसे तेज

1. B+ ब्लड ग्रुप

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ब्लड ग्रुप को लेकर एक रिसर्च किया गया था, जिसमें पाया गया कि सभी ब्लड ग्रुप में 'B पाजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है. इस रिसर्च में बताया गया कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों की सोचने-समझने की शक्ति अन्य लोगों के मुकाबले अच्छी होती है. जिन लोगों का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है उनके दिमाग में पेरिटोनियल और टेम्पोरल लोब के सेरिब्रम ज्याद एक्टिव होते हैं, जिससे इनकी याददाश्त तेज होती है और दिमाग एक्टिव रहता है.

2. O+ ब्लड ग्रुप

दूसरे नंबर पर आते हैं O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग. इन लोगों का दिमाग भी काफी तेज होता है. इस ब्लड ग्रुप के लोगों का ब्लड सर्कुलेशन दूसरों के मुकाबले अच्छा रहता है. इससे दिमाग में आक्सीजन का फ्लो अच्छा रहता है और याददाश्त अच्छी होती है. O पॉजिटिव लोगों के दिमाग में सेरिब्रम ज्यादा एक्टिव रहता है.

ब्लड ग्रुप A

ये लोग बहुत ही सेंसेटिव होते है अगर आपकी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आती है तो ये लोग गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते है.

शिवराजपुर बीच: यहां गोवा से आधे बजट में कर करेंगे खूब इंजाय, जाने से पहले ये जानना है जरूरी

यह गुजरात का ऐसा बीच जिसको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है ब्लू फ्लैग का दर्जा उन्हीं बीचों को मिलता है जो को दुनिया में बहुत ही साफ और स्वस्छ होते हैं. ऐसा ही एक बीच है शिवराजपुर बीच जो द्वारका से 11 किलोमटर दूर, ओखा से 23 किमी दूर स्थित अरब सागर के तट पर शिवराजपुर गांव के पास स्थित है. सफेद रेत के साथ यह बीच बहुत ही शांत और बहुत ही सुन्दर बीच है. यह समुद्र तट अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. यहां आप अपने बजट के अनुसार पैसा खर्च कर सकते हैं.

भारत का दूसरा सबसे लम्बा बीच

शिवराजपुर बीच द्वारका से 15 मिनट (11 किमी) की दूरी पर है जो की द्वारका – ओखा हाईवे पर स्थित है. यह समुद्री किनारा शिवराजपुर गांव तक फैला है जो लाइटहाउस और पथरीले समुद्री तटों के बीच में हैं. आपको बता दूं, यह बीच भारत का दूसरा सबसे लम्बा बीच है. गुजरात सरकार इस बीच को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके निर्माण पर काफी पैसे खर्च कर रही है.

शिवराजपुर बीच पर इंजाय के लिए चीजे

यहां पर करने के लिए बहुत सी चीजें है. आप यहां पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बोटिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हो. इसके अलावा आप तैराकी भी कर सकते हो और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हो. यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी बहुत खूबसूरत होता है आप वो भी देख सकते हो.

देखने के लिए निकटतम स्थान

शिवराजपुर समुद्र तट पर कैम्पिंग की सुविधा भी है इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आप यहाँ पर रात बिता सकते हो. आप 7 द्वीपों के दर्शन के लिए भी जा सकते हो द्वारका के आसपास द्वारका बीच, चोरवाड़ बीच, बेट द्वारका बीच भी स्थित है. आप वहां पर भी घूमने के लिए जा सकते हो. इसके अलावा आप श्री द्वारका धीश मंदिर, घोमती घाट, सुदामा सेतु, श्री शारदा पाठ, रुकमनी माता मंदिर, भड्केश्वर महादेव मंदिर, गीता मंदिर, गोपी तालाब, लाइट हाउस, हर्षद माता मंदिर भी दखने के लिए जा सकते हो.

ठहरने के लिए जगह

शिवराजपुर बीच, द्वारका और शिवराजपुर के बीच में स्थित है इसलिए आप द्वारका में होटल को बुक कर सकते हैं.

रेल मार्ग से - आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से द्वारका रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं. द्वारका रेलवे स्टेशन से ड्राइविंग करके 2 घंटे में बीच पर पहुंचा जा सकता है. यह ट्रेन अहमदाबाद, जामनगर और राजकोट से अच्छी तरह जुडी है.

हवाई मार्ग से - निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा है जो की बीच से 138 किमी दूर है. आप अहमदाबाद से जामनगर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं.

एसबीआई का शेयर बना रॉकेट, 180 रुपये से पहुंचा 500 के पार

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों ने पिछले तीन साल में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है. तीन साल में इस बैंक के शेयर ने 180 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. मार्च 2020 में एसबीआई का शेयर 180 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था. लेकिन अब यह शेयर 500 रुपए के स्तर को पार कर गया है. शुक्रवार को शेयर 1.41 फीसदी की गिरावट के साथ 505.50 रुपए पर बंद हुआ. हालांकि, स्टॉक वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 629.55 रुपये से 23 प्रतिशत से अधिक नीचे है. 15 दिसंबर, 2022 को इसने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ.

अन्य बैंकों की तुलना में यह कैसा है?

हालांकि स्टेट बैंक का शेयर पिछले एक साल में रिटर्न के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक से पीछे है. जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों ने एक साल में 51 फीसदी रिटर्न दिया है, वहीं यूनियन बैंक के शेयरों ने इस दौरान 65 फीसदी रिटर्न के साथ लिस्ट में टॉप किया है. पीएनबी और केनरा बैंक के शेयरों ने एक साल में क्रमशः 29 फीसदी और 22 फीसदी का रिटर्न दिया है.

तेजी जारी रह सकती है

इस पीएसयू बैंक के शेयर को लेकर ब्रोकरेज और जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी. विदेशी ब्रोकरेज जेफरीज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंकों का वैल्यूएशन काफी आकर्षक नजर आ रहा है. ठप भी इसके शीर्ष बैंक स्टॉक पिक्स में से एक है. टर्टल वेल्थ के संस्थापक और पोर्टफोलियो मैनेजर रोहन मेहता ने कहा कि एसबीआई हमारे लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है और हमारे फंड के लिए शीर्ष 3 होल्डिंग्स में से एक है.

बैंकिंग क्षेत्र दबाव मे

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से संपत्ति की गुणवत्ता के बजाय तरलता के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है. ब्रोकरेज ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आती है. एंजेल वन लिमिटेड के हेड एडवाइजरी अमर देव सिंह ने कहा कि एसबीआई ने इस तिमाही में तेज सुधार दर्ज किया है. कुल मिलाकर, वैश्विक मंदी और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नकारात्मक समाचारों के बारे में निवेशकों की बढ़ती आशंकाओं के कारण बैंकिंग क्षेत्र दबाव में आ गया है.

डीजल नहीं गाय-भैंस के गोबर से चलता है ये धांसू ट्रैक्टर

डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ब्रिटेन की एक कंपनी ने एक अनोखा आविष्कार किया है. उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो पूरी तरह गाय के गोबर पर चलता है. इटली की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी न्यू हालैंड ने गाय के गोबर से तैयार तरल मीथेन से चलने वाला ट्रैक्टर पेश किया है. यह किफायती खेती की दिशा में आशा की एक बड़ी किरण की तरह है. इस ट्रैक्टर को चलाने वाली गाय-भैंस के गोबर से लिक्विड मीथेन गैस बनाई जाती है. इस ट्रैक्टर में क्रायोजेनिक टैंक लगा है जो गैस को तरल रूप में बनाए रखता है.

ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी न्यू हॉलैंड का दावा है कि यह वर्जन डीजल ट्रैक्टर जितना ही पावरफुल है. कृषि में प्रमुख व्यय जुताई, बुवाई और सिंचाई पर आता है. आने वाले समय में इस खर्च को कम किया जा सकता है और किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है.

न्यू हॉलैंड ने लिक्विड मीथेन गैस से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है. यह गैस गाय और भैंस के गोबर से बनाई जाती है. इस प्रकार के ट्रैक्टर में डीजल भरने की जरूरत नहीं होती है. प्राकृतिक ईंधन से चलने वाला यह ट्रैक्टर पर्यावरण के लिहाज से भी मजबूत है. डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर कार्बन उत्सर्जन करते हैं. लंबे समय में ऐसा प्रयोग न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, बल्कि किसानों के लिए रोजगार और समृद्धि के रास्ते भी खोल सकता है.

न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर डीजल जितना शक्तिशाली है लेकिन मीथेन गैस पर चलता है. इसका 49-गैलन टैंक 62% कम नाइट्रस ऑक्साइड और 15% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है.

यह ट्रैक्टर 75 गाय के गोबर से अधिक समय तक चल सकता है. न्यू हॉलैंड टी 6 नाम के इस ट्रैक्टर का वजन 21100 पाउंड है, जबकि यह 180 हॉर्सपावर की ताकत देता है और खेतों में डीजल ट्रैक्टर की तरह काम करता है.

मीथेन गैस से चलने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे केविन ने कहा, श्यह ट्रैक्टर 10 मिनट में ईंधन भर सकता है और गैस की समस्या कभी नहीं होती.श उन्होंने कहा कि ईको फ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल में उनके प्रयास भले ही छोटे हों लेकिन अच्छी बात यह है कि वह कोशिश कर रहे हैं.

महिला सम्मेलन : मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला कर्मियों का किया सम्मान

आंगनबाड़ी केन्द्रों को गैस-चूल्हा और महिला समूह को बांटा गया ऋण

रायपुर. महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखण्ड के ग्राम हथबंद में आयोजित वृहद महिला सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 30 से अधिक महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान किया. उन्होनें 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों को गैस-चूल्हा तथा महिला कोष से विभिन्न स्व-सहायता समूह को 11 लाख रूपये से अधिक का ऋण वितरण भी किया. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

इस अवसर पर राज्य सभा की पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ल, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, पूर्व विधायक बलौदाबाजार जनक राम वर्मा, पूर्व विधायक दुर्ग श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाब हो रही हैं. महिलाएं खेती किसानी करने से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाकर विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से देश की सेवा कर रहीं है. राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं. हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण योजना शुरू की है. इस योजना के माध्यम से पात्र पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों की बैंक खातें में एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा. राज्य के प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं. इन सेंटरों के माध्यम से एक छत के नीचे महिलाओं को निःशुल्क विधिक चिकित्सा, परामर्श और आश्रय दिया जा रहा है. श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए.

Twitter से ब्लू टिक गायब हो गया तो क्या हुआ, ये टिप्स फलो करें और Instagram पर हो जाए वेरिफाइड

बीते शुक्रवार ट्विटर ने घोषणा की कि वह 1 अप्रैल से लेगेसी वेरिफाई प्रोग्राम को हटाना शुरू कर देगा और केवल सशुल्क कस्टमर्स और स्वीकृत संगठनों के सदस्यों को बैज रखने की अनुमति देगा. यानी कि अब आपको ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे. अगर आपका भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है तो परेशान होने कि जरुरत नहीं है. अभी भी आप अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किए वेरिफाइड हो सकते हैं. यहां हम बताते हैं कि कैसे कोई इंस्टाग्राम पर फ्री में वेरिफाई हो सकता है.

इंस्टाग्राम पर ब्लू टिप पाने के लिए इन शर्तों का करें पालन

इंस्टाग्राम पर वेरिफाइड बैज पाने के लिए यूजर का अकाउंट आथेंटिक होना चाहिए. साथ ही अकाउंट पब्लिक होना चाहिए. वहीं उपव में भी कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है. इतना ही नहीं, प्रोफाइल फोटो और अकाउंट एक्टिव भी होना चाहिए. आइए जानते हैं किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.

आपके पास ये जरूर होना चाहिए

1. आपके पास इंस्टाग्राम का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए
2. इंटरनेट कनेक्शन
3. अपना परिचय पत्र

इन स्टेप्स को फॉलो करें:

1. अपने स्मार्टफोन पर 'Instagram' खोलें.
2. ऐप के निचले हिस्से पर मौजूद 'Avatar' आइकन पर टैप करें.
3. अब ऊपर के दाहिने कॉर्नर पर मौजूद 3 हॉरिजॉन्टल लाइनों पर टैप करें.
4. सेटिंग सिलेक्ट करें और स्क्रोल करके 'Request Verification' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
5. अपना पूरा नाम, यूजर नेम और अपने आईडी प्रूफ का फोटो अपलोड करें और प्रक्रिया पूरी करें.
6. अब इंस्टाग्राम के रिप्लाई का इंतजार करें.

देश का सबसे बड़ा डाटा लीक!

इस बार एक-दो लाख नहीं, बल्कि 16.8 करोड़ लोग हुए शिकार

एक बड़े डेटा लीक (डेटा ब्रीच) का खुलासा हुआ है, जिसका यूजर्स की सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है. साइबराबाद पुलिस ने 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन पर करोड़ों यूजर्स का डेटा चोरी करने और उसे बेचने का आरोप है. इस गैंग पर सरकारी संस्थाओं और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन्स के डेटा लीक करने का आरोप है, जिसमें 2.55 लाख डिफेंस से जुड़े लोग हैं.

ये आरोपी एनर्जी और पावर सेक्टर, पैन कार्ड डाटा, सरकारी कर्मचारी, गैस और पेट्रोलियम, एचएनआई (हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स), डीमैट अकाउंट्स, स्टूडेंट डाटाबेस, वुमन डाटाबेस, ऐसे लोगों के डाटा जैसी कैटेगरी में जानकारी बेचते पाए गए हैं. इनके जरिए लोगों ने लोन और इंश्योरेंस के लिए आवेदन किया. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किया गया आरोपी एक सर्च इंजन कंपनी और इसी तरह के प्लेटफार्म के जरिए डाटा बेच रहा था.

इन लोगों का डाटा लीक में शामिल

दिल्ली से गिरफ्तार किए गए इन साइबर अपराधियों के पास 1.20 करोड़ लोगों का वाट्सएप डेटा है. इसके अलावा, इनपर फेसबुक यूजर्स का भी डाटा है, जिसकी संख्या 17 लाख है. इस डेटा में यूजर्स की उम्र, ईमेल, फोन नंबर और अन्य जानकारियां शामिल हैं. इसके अलावा, पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि दो करोड़ छात्रों का डाटा भी लीक हुआ है. इसमें CBSE की 12वीं क्लास के स्टूडेंट शामिल हैं. लीक हुए डेटा में उन लोगों का डेटा भी है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं. लीक डेटा में 1.47 करोड़ कार मालिक का डाटा भी है. इसके अलावा 11 लाख सरकारी एम्प्लाय की भी जानकारी लीक हुई है.

कितने में बिक गया डेटा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिमीनल्स ने 50 हजार लोगों का डाटा को 2000 रुपये में बेच दिया है. हालांकि इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल इस मामले और भी कई कड़ियों का खुलासा होना बाकी है.

एक्शन मोड में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक पर लगाया 30 लाख का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए एक चुनिंदा निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी वाले खातों की रिपोर्ट नहीं की, जो कि आरबीआई के 2016 के निर्देशों के अनुसार सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है.

21 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 तक निरीक्षण किया गया और बैंक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद, आरबीआई ने जुर्माना लगाया.

आरबीआई की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए जुर्माना लगाया गया है. उल्लेखनीय है कि करूर वैश्य बैंक ने दिसंबर तिमाही में 289 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था, जो पिछले साल की दिसंबर तिमाही में हुए मुनाफे से 30 फीसदी अधिक है.

आरबीआई पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है

इससे पहले रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली एजेंटों से संबंधित कुछ दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक को बैंक के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया था.

आरबीआई के नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और जुर्माना लग सकता है. बैंकों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से बचा जा सके.

छत्तीसगढ़ मॉडल की हुई तारीफ

- अपेक्स बैंक के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं सहित ग्रामीण विकास के कार्यों की दी जानकारी
- कोलकाता के बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान में ग्राहक परामर्श समिति की राष्ट्रीय बैठक

रायपुर. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में छत्तीसगढ़ मॉडल एक बार फिर छाया रहा. विभिन्न राज्यों से सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने विकास के लिए 'छत्तीसगढ़ मॉडल' को अनुकरणीय बताया. छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर ने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही न्याय योजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. राष्ट्रीय ग्राहक परामर्श समिति की बैठक में 15 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने 'छत्तीसगढ़ मॉडल' का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनहितैषी नीतियों से गांव का विकास, किसानों का विकास, खेतिहर मजदूरों का विकास, आदिवासियों, महिलाओं का विकास तथा अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों (अलाइड) का लगातार विकास हुआ है. किसानों को राहत देने वाली नीतियों, कार्यक्रमो और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गो-धन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं 65 प्रकार के वनोपजों का सर्मथन मूल्य पर खरीदी से गांवों में समृद्धि आई है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.

छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से को-आपरेटिव्ह बैंको से ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुनगर्ठन कर 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख समिति बनाई गई हैं. इन समितियों को आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराया गया. किसानों को सिंचाई पम्पों के लिए बिजली कनेक्शन, रियायती और निःशुल्क बिजली प्रदाय करने से फसल उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस साल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 23 लाख किसानों से 107.53 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है.

इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा को-आपरेटिव्ह बैंको के माध्यम से 21 हजार 946 करोड़ रूपए का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में अन्तरण किया गया. छत्तीसगढ़ खुशहाली और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है. बैठक में छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष चन्द्राकर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में बैंकों की भूमिका और उसके महत्व पर चर्चा करते हुए ग्राहक सेवा को सर्वोपरि बताया. राष्ट्रीय ग्राहक परामर्श समिति की बैठक में नाबार्ड सीजीएम मुम्बई, नाबार्ड सीजीएम पश्चिम बंगाल, बर्ड डायरेक्टर मालिक एवं बैंकर ग्रामीण संस्थान कोलकाता के डायरेक्टर श्रीमती अर्चना सिंह मौजूद थी.

75 वर्षीय किसान सत्यनारायण मधुमक्खी पालन से कर रहे हैं लाखों की कमाई, सिर्फ 10 बाक्स से शुरू किया था कारोबार

मुजफ्फरपुर का शिवराहा चतुर्भुज और इसके आसपास का इलाका जो कभी बाढ़ और अपराध के लिए जाना जाता था. अब मधुमक्खी कारोबार के लिए जाना जा रहा है. शिवराहा चतुर्भुज गांव के सत्य नारायण आजाद ने खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग कर 1970 में अनुदान में मिले दस बॉक्स मधुमक्खी से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की. और आज कारोबार में मिली सफलता को देखते हुए उनका पूरा परिवार और रिश्तेदार इससे जुड़ा गया है.

10 बॉक्स से 4 हजार बॉक्स तक पहुंचा कारोबार

कभी 10 बॉक्स से कारोबार की शुरुआत की थी. और आज आजाद के पास करीब 4 हजार मधुमक्खी बॉक्स है. जिसका सालाना कारोबार करोड़ों में होता है. इतना ही नहीं शिवराहा चतुर्भुज गांव के तकरीबन सभी लोग इस कारोबार से जुड़ गए हैं. आसपास के दर्जनों गांव जैसे शिवराहा चतुर्भुज, बेलहैया,मझौलिया मोहल्ला,समेत दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग मधुमक्खी पालन कर लाखों में आमदनी कर रहे हैं.

एक बॉक्स से होती है दो से ढाई हजार की कमाई

एक बॉक्स में लागत 4 से 5 हजार आता है और एक सीजन में दो से ढाई हजार की आमदनी प्रति बॉक्स होती है. 75 वर्षीय सत्यनारायण आजाद जब मधुमक्खी का प्लेट हाथों में लेते हैं तो काफी खुश दिखाई देते हैं और कारोबार में मिली सफलता की कहानी सुनाने लगते हैं. गांव के दूसरे लोग भी काफी उत्साहित होकर मधुमक्खी पालन और इससे होने वाली आमदनी की बात कहते हैं.

मधुमक्खी पालन करके समृद्ध हुआ पूरा गांव

1970 में मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने वाले सत्य नारायण आजाद बताते है कि ठीक से अब याद नही है. लेकिन खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग कर दस बॉक्स मधुमक्खी मिला था. उस समय इलाके में बाढ़ काफी आता था और अपराधिक घटना काफी होती थी. पहली बार दस बक्सा लेकर पंजाब गए और वहां से भी दस बक्सा मिला. फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हमारे गांव के सभी लोग और पूरा इलाका मधुमक्खी पालन करके समृद्ध हो गया है. वहीं मधुमक्खी पालन करने वाले शिवजी पासवान ने बताया की आज हमारे पास तीन सौ बॉक्स मधुमक्खी है. सालाना 7 से आठ लाख की आमदनी होती है. शुरुआत में आजाद जी के यहां ही काम करके हमने सीखा है.

पंजाब करते हैं सप्लाई और वहां से होता है इंपोर्ट

सत्य नारायण आजाद के बेटे बताते हैं कि आसपास के कई गांव के लोग इस कारोबार से जुड़ गए हैं. हमारे पास 4 हजार मधुमक्खी बॉक्स है. हमने अब मधु प्यूरीफायर मशीन भी लगा लिया है. पंजाब में सप्लाई करते हैं और वहा से इंपोर्ट होता है.

1 अप्रैल से इनकम टैक्स समेत इतने सारे नियमों में बदलाव

एक अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. आज से कॉमर्शियल सिलेंडर जहां 92 रुपए सस्ता हो गया है, वहीं कुछ दवाओं के दाम बढ़ गए हैं. इनकम टैक्स रिजीम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है और इसका असर हमारी जेबों पर क्या पड़ेगा.

2 रुपए सस्ता मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर

हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय की जाती है. आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 92 रुपए कम कर दिए गए हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम पहले की तरह रखे गए हैं. दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 2119.50 की जगह 2028 रुपए में मिल रहा है.

टैक्स छूट की सीमा बढ़ी

एक अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है. यानी जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है, उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी. नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है.

सीनियर सिटीजंस को फायदा

एक अप्रैल से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई है. मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए हो गई है. वहीं, जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह सीमा 7.5 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो गई है. अब स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक ब्याज दिया जाएगा.

जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब ज्यादा कर

अब पांच लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम की परंपरागत जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा. हालांकि, इसमें यूलिप (यूनिट लिंक्ड प्लान इंश्योरेंस) प्लान पर असर नहीं होगा. ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसीधारक पर होगा.

सोना खरीदना हुआ महंगा

सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत, चांदी पर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे इन गहनों के दाम बढ़ेंगे. एक अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. यानी इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों के तहत टैक्स चुकाना होगा.

6 अंक वाले हॉलमार्किंग अनिवार्य

एक अप्रैल 2023 से सोने के गहने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है. आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. यानी अब 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली जूलरी की बिक्री नहीं की जा सकती. देशभर में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं.

बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स

अब PF अकाउंट से PAN लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा. बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है. अब स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक मिलेगा ब्याज.

नए उत्सर्जन मानक लागू

देश में एक अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक लागू हो गए. इससे वाहन निर्माता कंपनियां बीएस-6 के दूसरे चरण के कड़े उत्सर्जन नियम के अनुसार गाड़ियां बनाना या पुरानी गाड़ियों के इंजन अपडेट करना शुरू कर चुकी हैं. इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ रही है. इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंनियों ने गाड़यों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है.

दवाएं महंगी

सरकार ने दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है. कीमत होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी. इससे दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की बीमारी से संबंधित दवाओं के खरीदने के लिए अधिक पैसे देने होंगे.

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू

1 अप्रैल से महिलाओं के लिए भारत सरकार की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू हो गई है. इस स्कीम के तहत 7.5 फीसदी का ब्याज भी मिलेगा. महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी. अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती हैं. 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी टैक्स

ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आमदनी पर अब 30 फीसदी टैक्स देना होगा. पहले 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा की कमाई पर ही टैक्स लगता था. इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिये मिलने वाली रकम की जानकारी भी देनी होगी.

डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG का लाभ नही

एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत टैक्स लगेगा. इससे निवेशकों को यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) का फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा. हालांकि इसका असर एक अप्रैल से पहले से खरीदे गए फंड्स पर नहीं पड़ेगा.

वाहन कबाड़ नीति लागू

एक अप्रैल से वाहन कबाड़ नीति लागू हो गई है. करने इसके तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है. सरकार ने साफ किया है कि कौन सी गाड़ियां कबाड़ में जाने वाली हैं. कबाड़ में भेजी जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा. इस नीति के तहत अगर कोई अपने वाहनों को कबाड़ में भेजता है और उसकी जगह नई गाड़ी खरीदता है तो उस नई गाड़ी पर 25 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी.

हुंडई लाई नई 7-सीटर MPV स्टारगेजर

Hyundai का साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में दबदबा बढ़ता जा रहा है. हुंडई हर सेगमेंट अपनी कार को लॉन्च कर रही है. अब हुंडई ने डच्ट सेगमेंट में भी एंट्री कर कर ली है. MPV सेगमेंट में भी एंट्री लेते हुए हुंडई ने आज 2023 Stargazer को लॉन्च किया है. कंपनी ने फिलहाल इसे थाईलैंड में लॉन्च किया है, लेकिन जल्द ही भारतीय बाजार में भी आने की उम्मीद है. हुंडई ने Stargazer को 6 और 7 सीटर ऑप्शन में लॉन्च किया है.

कंपनी ने 2023 हुंडई स्टारगेजर को ज्यादा प्रीमियम लुक और डिजाइन के साथ लॉन्च किया है. इस कार के रियर में H आकार की एलईडी लाइट बार लगाया गया है. इसकी साइट प्रोफाइल काफी हद तक स्टारिया डच्ट की तरह लगती है. हुंडई स्टारगेजर के टॉप स्पेक स्मार्ट ट्रिम्स में स्टाइलिश अलॉय व्हील और मिड-स्पेक वेरिएंट के साथ अलॉय व्हील दिया गया है.

इतनी है दमदार

कंपनी ने अपनी इस कार को 1.5-लीटर NA MPi पेट्रोल के सिंगल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है. जो 113 बीएचपी का पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस गाड़ी में IVT यूनिक गियरबॉक्स का सिंगल ऑप्शन दिया गया है. इस कार की लंबाई 4460 मिमी, चौड़ाई 1780 मिमी और ऊंचाई 1695 मिमी है.

इन फीचर से है लैस

हुंडई स्टारगेजर के फीचर की बात करें तो इसे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, 16-इंच अलॉय, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग से लैस किया गया है. इसके साथ ही इस कार में सेकेंड रो के लिए ट्रे टेबल,हुंडई का स्मार्ट सेंस ADAS सूट भी लगाया गया है.

इतनी है हुंडई स्टारगेजर की कीमत

हुंडई स्टारगेजर की कीमत की बात करें तो इसके बेस ट्रेंड वेरिएंट की कीमत 769,000 थाई बात (भारतीय रुपयों में 18.45 लाख), स्टाइल वेरिएंट की कीमत 829,000 थाई बात (भारतीय रुपयों में 19.89 लाख), स्मार्ट 7-सीटर की कीमत 869,000 थाई बात (भारतीय रुपयों में 20.85 लाख) है. वहीं इसके स्मार्ट 6-सीटर की कीमत 889,000 थाई बात (भारतीय रुपयों में 21.33 लाख) है.

भारत में कब होगी लॉन्च

हुंडई स्टारगेजर को फिलहाल अभी थाईलैंड में लॉन्च किया गया है. जहां पर इसकी टक्कर Suzuki Ertiga, Honda BR&V, Mitsubishi Xpander और Toyota Veloz जैसी गाड़ियों से होने वाली है. इस कार की भारत में लॉन्च होने को लेकर कंपनी का कहना है कि इसे 2024 में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा.

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, समझिए पूरा मामला

नई दिल्ली. चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सजा मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है. अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है. इससे पहले, राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था, यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय है. साल 2019 का ये मामला 'मोदी सरनेम' को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?" राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सजा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था.

उन्होंने कथित तौर पर ये कहा था, "इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?" राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं. वह भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है. इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था. भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है.

सजा के एलान के बाद याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं. दो साल की सजा के एलान से खुश है या नहीं सवाल ये नहीं है. ये सामाजिक आंदोलन की बात है. किसी भी समाज, जाति के खिलाफ बयान नहीं दिया जाना चाहिए और कुछ नहीं. बाकी हम अपने समाज में बैठकर आगे चर्चा करेंगे. राहुल गांधी की वकीलों की टीम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी समुदाय को अपने बयान से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे.

क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता

अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य, लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की दसवीं अनुसूची में है. इसमें दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं. इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है. इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है.

किन नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता?

- रशीद मसूद (कांग्रेस) को साल 2013 में एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें राज्यसभा की अपनी सदस्यता गँवानी पड़ी.
- लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई. उस समय वे बिहार में सारण से सांसद थे.
- जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी. उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे.
- समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता गँवानी पड़ी थी. रामपुर की एक अदालत ने उन्हें वर्ष 2019 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया था और तीन साल की सजा सुनाई थी.
- सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई. चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथपत्र दिया था.
- उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी. उन्हें 2013 के दंगा मामले में दो साल की सजा दी गई थी.

- मैं फिजिकल एजुकेशन के लिए जरूरी डायट और रूटीन नहीं कर पाती थी, भत्ते से मैं मजबूत बनूंगीः मुकेश्वरी
- प्रदेश के चार युवाओं को योजना शुरू होते ही मुख्यमंत्री के हाथों मिला बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश
- बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नही

मुझे नहीं पता था कि मैं आज आवेदन कर रही हूं और आज ही मुख्यमंत्री मुझे आदेश देंगेः पूजा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की है. मुख्यमंत्री ने योजना की शुरूआत के साथ ही चार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी जारी किया. मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृतिआदेश पाने वाले ये चार युवा अपने भविष्य को लेकर आशांवित हैं और इसके लिए मेहनत भी कर रहे है. बेरोजगारी भत्ते से इनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी. आइए जानते हैं कौन हैं ये चार युवा.

बेरोजगारी भत्ता

रायपुर जिले की रहने वाली पूजा चंद्रवंशी बी.एड. की छात्रा हैं. रायपुर के गुढिहारी की रहने वाली पूजा बेहद गरीब परिवार से हैं और बहुत ही मुश्किलों से शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं. अभी तक पूजा बीएड की मंहगी किताबें खरीद पाने में असमर्थ थीं और वो अपने सहपाठियों से किताबें लेकर पढ़ाई करती थीं. उन्हें ये किताबें वापस करने का दबाव होता था. बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में जानकारी मिलने पर पूजा ने आज ही आनलाइन इसके लिए आवेदन किया था और थोड़ी ही देर बाद उनका बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत भी हो गया.

मुकेश्वरी रायपुर के मोवा की रहने वाली एथलीट हैं और फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरीयर बनाना चाहती हैं. मुकेश्वरी को अपनी रेगुलर डाइट और अपनी रूटीन को मेंटन करने में काफी परेशानी होती है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए शरीर का फिट रहना बेहद जरूरी है. आर्थिक तंगी के बाद भी वो पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन शरीर का खयाल नहीं रख पाती थी. बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब मुकेश्वरी न सिर्फ अपनी अच्छी डायट ले सकेंगी बल्कि उन्हें पढ़ाई में भी आसानी होगी.

इसी तरह से गुढ़िहारी के रहने वाले कुणाल साहू कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं. आर्थिक हालात ठीक न होने से कुणाल बीसीए मंहगी किताबें खरीद नहीं पाते थे, बेरोजगारी भत्ते से ये परेशानी अब दूर हो गयी है.

रायपुर के ही कृष्णा नगर के रहने वाले दीपक निषाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके है और सिविस सर्विसेज में कैरीयर बनाने में जुटे हुए हैं. दीपक अपनी तैयारी को धार देने के लिए नई किताबें खरीदने से बचा करते थे, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ते से मिले पैसों से वो नई किताबें खरीद पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के और नजदीक पहुंच पाएंगे.

इन चारों युवाओं ने आज ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और इन्हें नहीं पता था कि आज ही इनका आवेदन स्वीकृत भी हो जाएगा. इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इन्हें पता चला कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें स्वीकृति आदेश प्रदान करेंगे. इन युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताते हुए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करन के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के इस मदद से वो जल्द ही रोजगार हासिल करेंगे.

लेख - मनोज सिंह, सहायक संचालक, रायपुर.

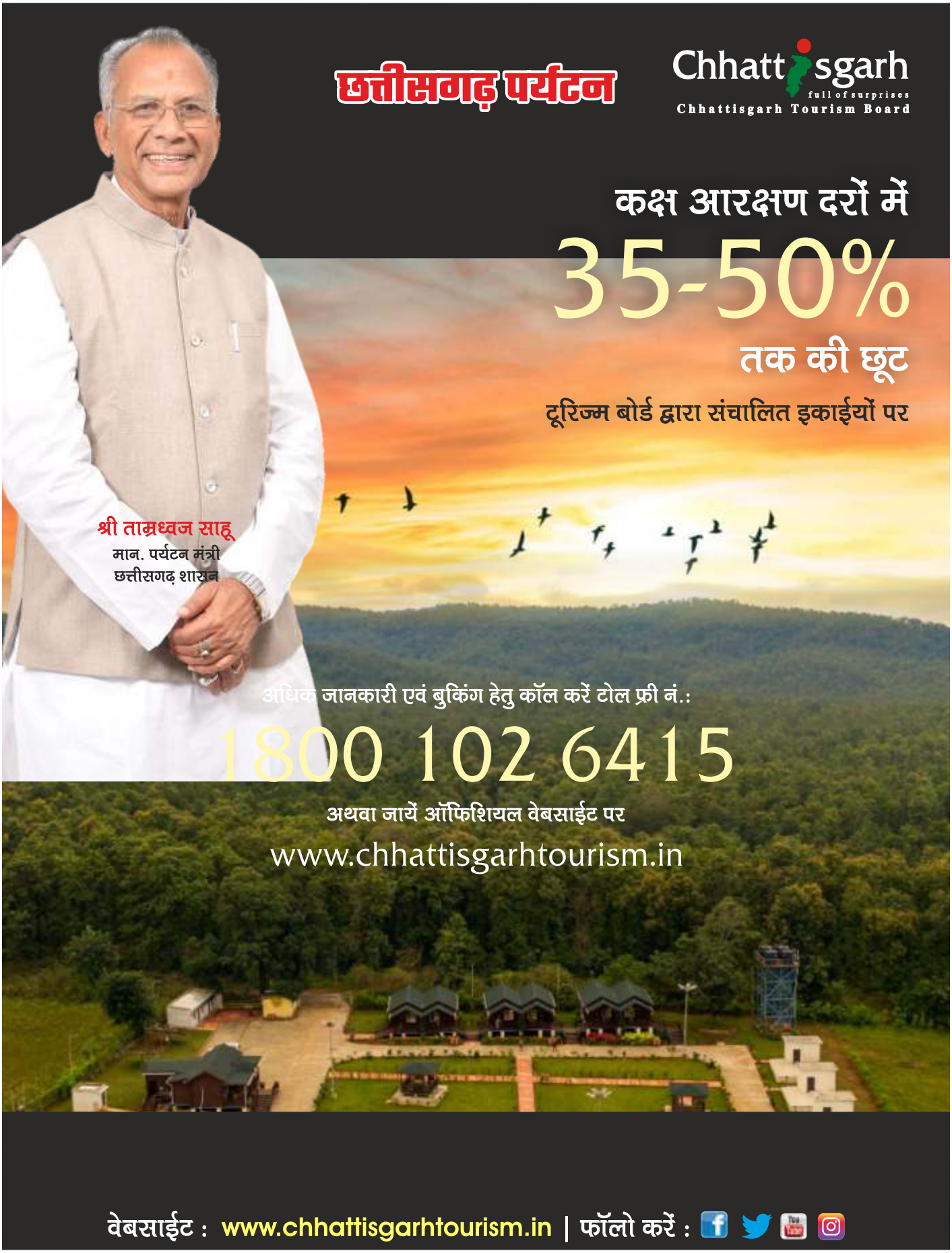
छत्तीसगढ़ पर्यटन
Chhattisgarh
full of surprises
Chhattisgarh Tourism Board
कक्ष आरक्षण दरों में
35-50%
तक की छूट
टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों पर
श्री ताम्रध्वज साहू
मान. पर्यटन मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु कॉल करें टोल फ्री नं.:
1800 102 6415
अथवा जायें ऑफिशियल वेबसाईट पर
www.chhattisgarhtourism.in
वेबसाईट : www.chhattisgarhtourism.in | फॉलो करें :

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

युवाओं को संबल

1 अप्रैल से

₹2,500 प्रतिमाह भत्ता

भत्ते की पात्रता

- आयु सीमा 18-35 वर्ष
- 2.5 लाख रु तक की परिवार की वार्षिक आय
- 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- मूल निवासी प्रमाणपत्र
- जन्मतिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट/प्रमाणपत्र
- 12वीं की मार्कशीट/प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- गत एक वर्ष की परिवार की आय का प्रमाणपत्र

पंजीकरण में सुगमता के लिए अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर घोषणानुसार भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा

3 वर्ष पुराने पंजीयन के नवीनीकरण का अंतिम तारीख बीत जाने के 2 महीने बाद तक का प्रावधान

नए पंजीयन के लिए

बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है

1 अप्रैल, 2023 से घर बैठे इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

https://berojgaribhatta.cg.nic.in/

छत्तीसगढ़ सरकार - भरोसे की सरकार

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprCg.gov.in

R.O. No. - 12409/35